UNIVERSITY NEWS 14 JUNE 2026

DAINIK JAGRAN

लवि : परियोजना की स्वीकृति से लेकर बिलिंग व भुगतान डिजिटल

जासं ● लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय (लवि) ने शोध परियोजनाओं और वित्तीय प्रबंधन को पारदर्शी बनाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। अब परियोजना की स्वीकृति से लेकर बिलिंग और भुगतान की पूरी ट्रैकिंग डिजिटल माध्यम से होगी। मुख्य शोधार्थियों को फंड का विवरण, स्वीकृति पत्र और सभी इनवाइस अनिवार्य रूप से समर्थ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।

लवि के कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने बताया कि नई डिजिटल प्रणालियों के एकीकरण और निश्चित समय-सीमा से अब फाइलों की देरी बीते दिनों की बात हो जाएगी। परियोजनाओं के तहत जूनियर रिसर्च फेलो, पीडीएफ या प्रोजेक्ट स्टाफ की भर्ती के लिए पांच-सदस्यीय आधिकारिक चयन समिति का गठन किया गया है। इसमें संबंधित संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, मुख्य अन्वेषक, बाहरी विशेषज्ञ और उपकुलसचिव (प्रोजेक्ट) शामिल होंगे, जिससे चयन प्रक्रिया में एकरूपता आएगी। उपकरणों और सामग्रियों की खरीद के लिए सरकारी नियमों और जेम पोर्टल की प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन अनिवार्य किया गया है।

50 हजार रुपये तक की सीधी

शोध परियोजनाओं व वित्तीय प्रबंधन को पारदर्शी बनाने को एसओपी जारी, फंड का विवरण पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी

खरीद, 50 हजार से 10 लाख तक के लिए न्यूनतम तीन निर्माताओं के बीच तुलनात्मक प्रक्रिया व 10 लाख से अधिक के लिए आनलाइन निविदा आमंत्रित की जाएगी। बिना सक्षम स्तर की पूर्व-स्वीकृति के की गई किसी भी खरीद का भुगतान देय नहीं होगा। विभागाध्यक्ष और रजिस्ट्रार स्तर पर प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए मात्र एक से दो दिन का समय तय किया गया है।

वेंडरों के बिल और शोधार्थियों की फेलोशिप फाइल को डीलिंग असिस्टेंट, लेखाधिकारी और वित्त अधिकारी द्वारा अधिकतम तीन से सात दिनों के भीतर किया जाएगा। 50 हजार रुपये से अधिक के बिलों पर कुलपति की स्वीकृति आवश्यक होगी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपयोगिता प्रमाण पत्र और व्यय विवरण को अधिकतम सात से 10 दिनों के भीतर सत्यापित कर फंडिंग एजेंसी को भेजा जाएगा।

VOICE OF LUCKNOW

लविवि ने जारी की नयी एसओपी

● शोध परियोजनाओं व वित्तीय प्रबंधन को पारदर्शी व गतिमान बनाने के लिए कुलपति ने लिया निर्णय

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने अकादमिक अनुसंधान, तकनीकी विकास और शोध परियोजनाओं के समयबद्ध निष्पादन के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। विश्वविद्यालय के कुलपति के दिशानिदेर्शानुसार तैयार की गई यह एसओपी परियोजना प्रस्तावों की प्रस्तुति, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियों, बजट उपयोग और रिपोर्टिंग को पूरी तरह पारदर्शी, सरल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर केंद्रित बनाएगी।

इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि यह नई एसओपी प्रशासनिक लालफीताशाही को खत्म कर हमारे शोधकर्ताओं और मुख्य अन्वेषकों (पीआई) को एक तनावमुक्त और पारदर्शी माहौल देगी। डिजिटल प्रणालियों के एकीकरण और निश्चित समय-सीमा से अब फाइलों की देरी बीते दिनों की बात हो जाएगी, जिससे विश्वविद्यालय में 'लाइट एंड लर्निंग' का हमारा संकल्प और सुदृढ़ होगा।

एस ओपी की मुख्य विशेषताएं और चरण: नई व्यवस्था के तहत पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट चरणों और समय-सीमा में विभाजित किया गया है। डिजिटल एकीकरण सामर्थ पोर्टल परियोजना की स्वीकृति से लेकर बिलिंग और भुगतान की पूरी ट्रैकिंग डिजिटल माध्यम से होगी। मुख्य अन्वेषकों को फंड का विवरण, स्वीकृति पत्र और सभी बीजक अनिवार्य रूप से सामर्थ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

परियोजनाओं के तहत जूनियर रिसर्च फेलो, पीडीएफ या प्रोजेक्ट स्टाफ की भर्ती के लिए विश्वविद्यालय द्वारा एक पांच-सदस्यीय आधिकारिक चयन समिति का गठन किया गया है। इसमें संबंधित संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, मुख्य अन्वेषक, बाहरी विशेषज्ञ और उपकुलसचिव (प्रोजेक्ट) शामिल होंगे, जिससे चयन प्रक्रिया में एकरूपता आएगी।

HINDUSTAN

शोध से भुगतान तक डिजिटल ट्रैकिंग

एलयू

लखनऊ, कार्यालय संवाददाता। लखनऊ विश्वविद्यालय ने अकादमिक अनुसंधान, तकनीकी विकास और शोध परियोजनाओं के समयबद्ध निष्पादन के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जेपी सैनी के दिशा निर्देशानुसार तैयार की गई यह एसओपी परियोजना प्रस्तावों की प्रस्तुति, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियों, बजट उपयोग और रिपोर्टिंग को पूरी तरह पारदर्शी, सरल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर केंद्रित बनाएगी।

कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने कहा कि हमारा लक्ष्य लखनऊ विश्वविद्यालय को वैश्विक स्तर पर अनुसंधान का एक अग्रणी केंद्र बनाना है। नई व्यवस्था के तहत पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट चरणों और समय-सीमा में विभाजित किया गया है। परियोजना की स्वीकृति से लेकर बिलिंग और भुगतान की पूरी ट्रैकिंग डिजिटल माध्यम से होगी। मुख्य अन्वेषकों को फंड का विवरण, स्वीकृति पत्र और सभी बीजक अनिवार्य रूप से समर्थ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

- एलयू ने पांच सदस्यीय चयन समिति बनाई
- समिति प्रक्रिया को स्पष्ट और पारदर्शी बनाएगी

उपकरणों और सामग्रियों की खरीद के लिए सरकारी नियमों और जेम पोर्टल का कड़ाई से अनुपालन अनिवार्य किया गया है। इसी क्रम में 50,000 से अधिक के बिलों पर कुलपति की अंतिम प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक होगी।

AMRIT VICHAR

लविवि में 50 हजार से अधिक के बिल कुलपति करेंगे स्वीकृत

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

● वित्तीय प्रबंधन के लिए जारी की नई एसओपी

अमृत विचार : लखनऊ विश्वविद्यालय ने अकादमिक अनुसंधान, तकनीकी विकास और शोध परियोजनाओं के समयबद्ध निष्पादन के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। कुलपति के दिशानिर्देशानुसार तैयार की गई यह एसओपी परियोजना प्रस्तावों की प्रस्तुति, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियों, बजट उपयोग और रिपोर्टिंग को पूरी तरह पारदर्शी, सरल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर केंद्रित बनाएगी। कुलपति ने कहा कि हमारा लक्ष्य लखनऊ विश्वविद्यालय को वैश्विक स्तर पर अनुसंधान का एक अग्रणी केंद्र बनाना है। यह नई एसओपी प्रशासनिक लालफीताशाही को खत्म कर हमारे शोधकर्ताओं और मुख्य अन्वेषकों को एक तनावमुक्त और पारदर्शी माहौल देगी। लविवि में 50 हजार या इससे अधिक के बिल अब कुलपति स्वीकृत करेंगे।

पोर्टल के माध्यम से खरीद: उपकरणों और सामग्रियों की खरीद के लिए सरकारी नियमों और पोर्टल का कड़ाई से अनुपालन अनिवार्य किया गया है। 50 हजार तक की सीधी खरीद, 50 हजार से 10 लाख तक के लिए न्यूनतम तीन निर्माताओं के बीच एल 1 तुलनात्मक प्रक्रिया, तथा 10 लाख से अधिक के लिए ऑनलाइन निविदा आमंत्रित करना अनिवार्य होगा। बिना सक्षम स्तर की पूर्व-स्वीकृति के की गई किसी भी खरीद का भुगतान देय नहीं होगा।

एसओपी की मुख्य विशेषताएं और चरण

- नई व्यवस्था के तहत पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट चरणों और समय-सीमा में विभाजित किया गया है जिसमें डिजिटल परियोजना की स्वीकृति से लेकर बिलिंग और भुगतान की पूरी ट्रैकिंग डिजिटल माध्यम से होगी। मुख्य अन्वेषकों को फंड का विवरण, स्वीकृति पत्र और सभी बीजक अनिवार्य रूप से समर्थ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

मानव संसाधन चयन में पारदर्शिता

- परियोजनाओं के तहत जूनियर रिसर्च फेलो, पीडीएफ या प्रोजेक्ट स्टाफ की भर्ती के लिए विश्वविद्यालय द्वारा एक पांच-सदस्यीय आधिकारिक चयन समिति का गठन किया गया है।

AMAR UJALA

नई एसओपी जारी, शोध परियोजनाओं को लगेंगे पंख

लखनऊ। लविवि ने अनुसंधान और विकास के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसका उद्देश्य शोध परियोजनाओं का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करना और पारदर्शिता बढ़ाना है। यह एसओपी प्रस्तावों, वित्तीय स्वीकृतियों और रिपोर्टिंग को डिजिटल बनाएगी। कुलपति जेपी सैनी ने कहा कि इससे फाइलों की देरी समाप्त होगी। पूरी प्रक्रिया को चरणों और समय-सीमा में बांटा गया है। मुख्य अन्वेषकों को फंड विवरण समर्थ पोर्टल पर अपलोड करना होगा। जूनियर रिसर्च फेलो या प्रोजेक्ट कर्मचारी भर्ती के लिए पांच-सदस्यीय चयन समिति बनेगी। है। (संवाद)

HINDUSTAN

सहभागिता शुल्क 20 जून तक जमा कर सकेंगे

लखनऊ विश्वविद्यालय ने केंद्रीय प्रवेश प्रणाली के अंतर्गत सहभागिता शुल्क जमा करने की तिथि 20 जून तक बढ़ा दी है। संयुक्त महाविद्यालय में संचालित सेल्फ फाइनेंस कोर्स केंद्रीय प्रवेश प्रणाली से प्रवेश लेना चाहते है, वे पाठ्यक्रम विवरण सहभागिता शुल्क जमा कर सकते है।

HINDUSTAN TIMES

LU rolls out digital SOP to fast-track research funds

LUCKNOW : Researchers at Lucknow University will no longer be required to run from pillar to post, chasing files and waiting months for project funds. The university has rolled out a new Standard Operating Procedure (SOP) aimed at cutting red tape and putting research money, recruitment and purchases on a strict digital clock.

HINDUSTAN

रिकार्ड 30 तक होंगे अपलोड

लखनऊ। विवि डिग्री कॉलेजों को 30 जून तक विद्यार्थियों के शैक्षिक रिकार्ड को यूजीसी के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।